भारत का संविधान

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions

Tansukh Paliwal
LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws

Sample Preview

Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

Click Here to Buy Linking Publications

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, **"वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें"**. This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"**Paperathon**." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- **Tansukh Paliwal**

Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

INDEX		
Sr. No.	Subjects	Page No.
1.	Range – Part wise	4
2.	Prelims MCQs	5-101
3.	Mains Questions	103-165
4.	Interview Questions	166-176

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

Constitution of India		
Part.	**Range Part wise**	***Articles***
-	प्रस्तावना	-
I	संघ और उसके क्षेत्र	1 – 4
II	नागरिकता	5 -11
III	मौलिक अधिकार	12 – 35
IV	राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत	36 – 51
IV A	मौलिक कर्तव्य	51A
V	संघ	52 – 151
VI	राज्य	152 – 237
VII	पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य	Repealed
VIII	संघ राज्यक्षेत्र	239 – 242
IX	पंचायत	243 – 243O
IXA	नगरपालिकाएँ	243P– 43ZG
IXB	सहकारी समितियाँ	243ZH– 243ZT
X	अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र	244 – 244A
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 – 263
XII	वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद	264 – 300A
XIII	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 – 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 – 323
XIVA	न्यायाधिकरण	323A – 323B
XV	निर्वाचन	324 – 329A
XVI	कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	330 – 342A
XVII	राजभाषा	343 – 351
XVIII	आपातकालीन प्रावधान	352 – 360
XIX	प्रकीर्ण	361 – 367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान	369 – 392
XXII	संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन	393 – 395
–	अनुसूचियों	I-XII

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

संविधान का इतिहास और स्रोत

1. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था ?
(a) काउन्सिल ऑफ स्टेट्स
(b) निचला सदन
(c) द्वैध शासन (Dyarchy)
(d) यह सभी

[UK PSC(J) 2023]
Ans. [d]

स्पष्टीकरण- भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने देश के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की थी। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई, अर्थात, प्रशासकों के दो वर्ग थे अर्थात् कार्यकारी पार्षद और मंत्री। इसके अलावा, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना दो सदनों यानी लोकसभा और राज्य परिषद के साथ की गई थी।

2. निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के घरेलू क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है ?
(a) अनुच्छेद 2(7)
(b) अनुच्छेद 23
(c) अनुच्छेद 3
(d) अनुच्छेद 4

[UK PSC(J) 2023]
Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान- अनु.2 संयुक्त राष्ट्र चार्टर ।
स्पष्टीकरण- अनु.2 कुछ सिद्धांत प्रदान करता है जिसके अनुसार संघ और उसके सदस्य कार्य करेंगे। अनुच्छेद 2(7) में कहा गया है कि प्रस्तुत घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा गया है वह संयुक्त राष्ट्र को किसी भी राज्य के ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा, जो मूलतः उसके आन्तरिक अधिकार क्षेत्र में आते हों, और न ही वह सदस्य राज्यों से अपने ऐसे मामले प्रस्तुत घोषणा पत्र के अधीन निपटाने के लिए संघ के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, परन्तु अध्याय 7 में किसी राज्य को किसी कार्य के लिए बाध्य करने के जो उपाय बताए गए है, उनको लागू किए जाने पर इस सिद्धांत का कोई असर नहीं पड़ेगा।

3. निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ?
(a) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम- 1947
(b) भारतीय काउन्सिल अधिनियम-1909
(c) दि कम्युनल अवार्ड - 1930
(d) संविधान सभा की प्रथम बैठक - 1946

[UK PSC(J) 2023]
Ans [c]

स्पष्टीकरण- सांप्रदायिक अधिनिर्णय (मैकडॉनल्ड अधिनिर्णय के रूप में भी जाना जाता है) ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को बनाया गया था और गोलमेज सम्मेलन (1930-32) के बाद इसकी घोषणा की गई थी। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत के पीछे का कारण यह था कि रामसे मैकडोनाल्ड ने खुद को 'भारतीयों का मित्र' माना था और इस तरह वे भारत के मुद्दों को हल करना चाहते थे।

4. संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी?
(a) 8 दिसंबर (b) 9 दिसंबर
(c) 10 दिसंबर (d) 12 दिसंबर

[BJS 2020]
Ans.[b]

स्पष्टीकरण- भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान हॉल, नई दिल्ली में हुई थी। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। बाद में डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।

5. निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है?
(a) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को
(b) भारत की संसद को
(c) भारत के राष्ट्रपति को
(d) भारत के संविधान को

[UPPCS(J) 2015]
Ans. [d]

स्पष्टीकरण:- भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सरकार के सभी अंग अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान से अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करते हैं। कोई भी संवैधानिक मर्यादाओं को पार नहीं कर सकता है और यह उसी के अनुसार शक्ति का वितरण करता है।

6. संविधान बनाने का काम कब पूर्ण हो गया था?
(a) 26 नवंबर, 1949
(b) 26 जनवरी, 1950
(c) 15 अगस्त, 1947
(d) 25 नवंबर, 1949

[BJS 2020]
Ans.[a]

स्पष्टीकरण- संविधान सभा के विचार को सामने रखने वाले कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत की और इस तरह इतिहास रचा। लोकतांत्रिक भारत का सर्वोच्च कानून 1946 से 1950 तक विधानसभा द्वारा तैयार किया गया था और अंततः **26 नवंबर 1949** को w.e.f. 26 जनवरी 1950 अपनाया गया था, जिसे भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

7. मौलिक अधिकारों की संकल्पना को किस संविधान से लिया गया था?
(a) ब्रिटिश संविधान
(b) अमेरिकी संविधान
(c) ऑस्ट्रेलियाई संविधान
(d) कनाडा का संविधान

[BJS 2020]
Ans.[b]

लिंकिंग प्रावधान: भाग III (अनुच्छेद12-35) भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- भारत में मौलिक अधिकारों का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान का भाग III, जिसका शीर्षक "मौलिक अधिकार" है। भाग III के तहत कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं-
(1) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
(2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
(4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
(5) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
(6) संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

8. भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिये गये हैं ?
(a) अमरीका (b) आयरलैंड
(c) ब्रिटेन (d) कोलम्बिया

[Raj. JLO 2019]
Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान- भाग IV (अनुच्छेद 36-51) भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- भाग IV (अनुच्छेद 36-51) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इन्हें आयरलेंड संविधान से अपनाया गया है, और हमारे लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान में शामिल किया गया है। ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

9. किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में 'मूलभूत अधिकार' एवं 'न्यायिक पुनरावलोकन' की अवधारणा ली गई है ?
(a) ऑस्ट्रेलिया
(b) ब्रिटेन
(c) संयुक्त राज्य अमेरिका
(d) जापान

[Raj. JLO 2019]
Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान- अनुच्छेद 13, भाग III (अनुच्छेद 12-35) L/w 358, 359 भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को संविधान में स्पष्ट रूप से नामित नहीं किया गया है लेकिन यह अनुच्छेद 13 में निहित है। यह न्यायालय की शक्ति है जिसके तहत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम की संवैधानिकता की जाँच करता है और भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12-35 शामिल है, जो कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत में मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन दोनों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है।

10. भारतीय संविधान की समीक्षा करने के लिए बने प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
(a) न्यायमूर्ति वेंकटचलैया
(b) न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह
(c) न्यायमूर्ति ए० एम० अहमदी
(d) न्यायमूर्ति के० जी० बालाकृष्णन

[BJS 2020]
Ans.[a]

स्पष्टीकरण- 90 के दशक के अंत में पूरे संविधान की पुनर्विलोकन करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान के कामकाज की पुनर्विलोकन के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था।

11. भारत में आपातकाल की उद्घोषणा के संविधान का संरचनात्मक भाग काफी हद तक निम्न से लिया गया है:
(A) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(B) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(C) पिट्स अधिनियम, 1784
(D) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

[OJS 2016]
Ans [B]

स्पष्टीकरण:-आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग अठारह में निहित हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी या सभी भारतीय राज्यों में आपातकालीन शासन लागू करने की शक्ति है यदि "युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह" से भारत के किसी हिस्से या पूरे हिस्से की सुरक्षा को खतरा हो।
संविधान का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से आपातकाल की उद्घोषणा का संरचनात्मक हिस्सा, काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है।

12. निम्नलिखित में से किसने भारत में द्वैध शासन की स्थापना की?
(A) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
(B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(C) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

[OJS 2016]
Ans [B]

स्पष्टीकरण:-भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने भारत में द्वैध शासन, दोहरी सरकार की एक प्रणाली की शुरुआत की। 1919 के मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित में विभाजित करके प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। इसने भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसने भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया।

13. भारतीय संविधान में विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस संविधान से लिया गया था ?
(a) अमेरिका
(b) जापान
(c) इंग्लैण्ड
(d) कनाडा

[Raj. JLO 2013-14]
Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान :-
1. **अनुच्छेद 14-18 -** समानता का अधिकार।
2. **अनुच्छेद 39(घ) -** समान कार्य के लिए, समान वेतन।
3. **अनुच्छेद 14** - क) विधि के समक्ष समानता, ख) विधि के समक्ष समान संरक्षण।

स्पष्टीकरण:- अनुच्छेद 14 - यह प्रावधान सभी व्यक्तियों को चाहे नागरिक हो या विदेशी, अधिकार प्रदान करता है। 'विधि के समक्ष समानता' की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है जबकि 'विधियों के समान संरक्षण' की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है।

14. भारतीय संविधान में अवधारणा किस देश के एकल नागरिकता की संविधान से ली गई है ?
(a) फ्राँस
(b) कनाडा
(c) यू.के.
(d) यू. एस. ए.

[Raj. JLO 2019]
Ans [c]

लिंकिंग प्रावधान- अनुच्छेद 5-11 भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- आमतौर पर एक संघीय राज्य में नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन भारत में केवल एकल नागरिकता है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है, चाहे उसका निवास स्थान या जन्म स्थान कुछ भी हो। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को यू.के. के संविधान से अपनाया गया था।

15. निम्न में से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है ?
(a) शासन की संसदीय प्रणाली
(b) एकल नागरिकता
(c) लोकसभा अध्यक्ष
(d) मूल अधिकार

[Raj. JLO 2019]
Ans [d]

लिंकिंग प्रावधान- भाग III L/w 358, 359 भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12-35 शामिल है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है और सरकार के संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, लोकसभा के अध्यक्ष की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है।

16. निम्न में से किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्ट मिनिस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया ?
(a) यू.एस.ए.
(b) ब्रिटेन
(c) कनाडा
(d) आयरलैंड

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

संवैधानिक सभा

22. संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ -
(a) 24 January, 1950
(b) 26 November, 1949
(c) 17 October, 1949
(d) 10 December, 1948

[UPPCS(J) 2018]
Ans. [a]

स्पष्टीकरण:- भारत के संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकार किया गया था और माननीय सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। कुल मिलाकर, 284 सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे।

24. संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था ?
(a) डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा
(b) डॉ. अम्बेडकर
(c) डॉ. राधाकृष्णन
(d) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

[Raj. JLO 2013-14]
Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान:-
1. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
2. बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। (मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया)
3. सबसे उम्रदराज सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
   यह फ्रांसीसी प्रथा का पालन करके किया जाता है।

स्पष्टीकरण:- डॉ.सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया और हरेंद्र कुमार मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष बने।

25. संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था ?
(a) 25 नवम्बर, 1949
(b) 26 नवम्बर, 1949
(c) 27 नवम्बर, 1949
(d) 28 नवम्बर, 1949

[Raj. JLO 2013-14]
Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान:-
1. संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
2. 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।
3. डॉ. बीआर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
4. संविधान सभा ने 11 सत्र आयोजित किए और संविधान बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे।

स्पष्टीकरण:- गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शासित होता है जिसे 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।

26. संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ?
(a) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
(b) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(c) सरदार वल्लभभाई पटेल
(d) मौलाना अबुल कलाम आजाद

[Raj. JLO 2019]
Ans [b]

स्पष्टीकरण- भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफ़ारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में किया गया था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।

27. भारत के संविधान को स्वीकार किया :
(a) गवर्नर जनरल ने
(b) ब्रिटिश क्राउन ने
(c) संविधान सभा ने
(d) भारतीय संसद ने

[Raj. JLO 2019]
Ans [c]

स्पष्टीकरण- संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

प्रारूप समिति

28. संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा?
(a) जवाहरलाल नेहरू
(b) बी० आर० अंबेडकर
(c) बी० एन० राव
(d) महात्मा गाँधी

[BJS 2020]
Ans.[a]

लिंकिंग प्रावधान: भारत का संविधान की प्रस्तावना ।
स्पष्टीकरण- जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, 1946 को 'उद्देश्य प्रस्ताव' का प्रस्ताव रखा। 'प्रस्ताव' ने उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और 'राष्ट्रीय लक्ष्यों' को निर्धारित किया। 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित 'उद्देश्य प्रस्ताव' अंततः भारत के संविधान की प्रस्तावना बन गया।

29. भारतीय संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) के अध्यक्ष कौन थे ?
(a) Dr. Rajendra Prasad/ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(b) Dr. B. R. Ambedkar/ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
(c) M. K. Gandhi/ एम. के. गाँधी
(d) Moti Lal Nehru/ मोतीलाल नेहरु

[Raj. JLO 2013-14]
Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान:-
संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। बी.आर.अम्बेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उन्हें "भारत के संविधान के जनक" के रूप में मान्यता प्राप्त है।
स्पष्टीकरण:-
मसौदा समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को डॉ. बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में की गई थी। संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे।

30. संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या थीं :
(a) 7 (b) 8
(c) 10 (d) 5

[Raj. JLO 2019]
Ans [a]

स्पष्टीकरण- 29 अगस्त 1947 को, भारतीय संविधान के प्रारूपण-समिति की नियुक्ति की गई और इसमें सात सदस्य थे यानी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी, बी.आर. अम्बेडकर (प्रारूपण समिति के अध्यक्ष), के.एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान।

Sample Preview
Click Here to Buy Linking Publications

भारत का संविधान

मुख्य परीक्षा प्रश्न – हल

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भारत का संविधान

संविधान, संविधानवाद और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. भारत सरकार अधिनियम, 1935 की मुख्य विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

[BJS 1980]

उत्तर - भारत सरकार अधिनियम, 1935 की मुख्य विशेषताएं

भारत सरकार अधिनियम, 1935 एक महत्वपूर्ण विधि थी जिसने भारत के वर्तमान संविधान के लिए आधार तैयार किया। इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से अधिक स्वशासी संरचना की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, हालांकि यह अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता देने से पीछे रह गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. अधिनियम में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों से मिलकर एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया। हालाँकि, यह महासंघ कभी प्रभाव में नहीं आया क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं।
2. अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, जिससे प्रांतों को अधिक शक्ति और जिम्मेदारी प्रदान की गई। प्रांतीय विधायिकाओं को स्थानीय मामलों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण दिया गया था, और राज्यपालों को कुछ आरक्षित मामलों को छोड़कर, मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता थी।
3. अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, जिसमें संघीय विधानसभा (निचला सदन) और राज्य सभा (उच्च सदन) शामिल थीं। कुछ प्रांतों को एक विधान सभा और एक विधान परिषद के साथ द्विसदनीय विधायिकाएँ भी दी गईं।
4. जबकि द्वैध शासन प्रणाली (भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा प्रांतीय स्तर पर शुरू की गई) को प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था, इसे 1935 अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर पेश किया गया था। विषयों को "संघीय" और "प्रांतीय" सूचियों में विभाजित किया गया था, कुछ "आरक्षित" विषयों का प्रबंधन गवर्नर-जनरल द्वारा किया जाता था और "स्थानांतरित" विषयों का प्रबंधन विधायिका के लिए जिम्मेदार मंत्रियों द्वारा किया जाता था।
5. इस अधिनियम ने मतदाताओं का विस्तार किया, जिससे लगभग 10% भारतीय आबादी को मतदान का अधिकार मिला। यह एक उल्लेखनीय वृद्धि थी, हालाँकि अभी भी जनसंख्या के एक छोटे से भाग को मतदान करने की अनुमति थी।
6. इस अधिनियम ने भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती था। संघीय न्यायालय के पास प्रांतों के बीच विवादों को सुलझाने और उच्च न्यायालयों से अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र था।
7. अधिनियम ने सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए विषयों की अलग-अलग सूची के साथ, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया।

2. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने भारत के वर्तमान संविधान में क्या योगदान दिया? प्रत्येक के सुसंगत प्रावधानों को इंगित करते हुए चर्चा करें।

[BJS 1986]

उत्तर - भारत सरकार अधिनियम, 1935 को अक्सर भारत के संविधान का अग्रदूत माना जाता है। इसके कई प्रावधानों ने भारतीय संविधान में पाए जाने वाले सिद्धांतों और संरचनाओं के लिए आधार तैयार किया:

- अधिनियम ने केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के साथ एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा। संविधान ने एक संघीय ढांचे को अपनाया जहां सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है। संविधान में उल्लिखित शक्तियों का विभाजन 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित विभाजन के समान है।
- अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर संघीय विधानसभा और राज्य सभा के साथ एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की। भारतीय संविधान ने एक द्विसदनीय संसद की भी स्थापना की जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल थी।
- राज्यपाल प्रांतीय सरकार का प्रमुख होता था, जिसके पास कुछ क्षेत्रों में अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति होती थी। राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं, विशेषकर आपात स्थिति में। राज्य की कार्यपालिका शाखा के प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका संविधान में जारी है, यद्यपि उसकी शक्तियों और सीमाओं को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- गवर्नर-जनरल के पास आपात की घोषणा करने और संकट के समय प्रांतीय प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए व्यापक शक्तियाँ थीं। संविधान में आपात प्रावधान (अनुच्छेद 352, 356, और 360) की जड़ें 1935 के अधिनियम में हैं।
- इस अधिनियम ने भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका की ओर पहला कदम था। भारतीय संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को अपनाया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करके इसका विस्तार किया।
- अधिनियम में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों की देखरेख के लिए केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) के लिए प्रावधान बनाए रखा गया है, जिससे लोक सेवाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

3. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

[BJS 1980, 1991]

उत्तर - भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक विधि था जिसके कारण 15 अगस्त, 1947 को दो स्वतंत्र अधिराज्यों, भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत को चिह्नित किया और भारत और पाकिस्तान के संप्रभु राष्ट्रों की नींव रखी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- इस अधिनियम में भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति और देश को दो अलग-अलग अधिराज्यों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रावधान किया गया। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया था।
- प्रत्येक अधिराज्य को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया गया था यदि वह चाहे।
- भारत और पाकिस्तान दोनों को पूर्ण विधायी संप्रभुता प्रदान की गई। दोनों अधिराज्यों की विधायिकाओं को ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप के बिना अपने स्वयं के संविधान बनाने और स्वयं शासन करने का अधिकार दिया गया।
- इस अधिनियम ने भारत में वायसराय के पद को समाप्त कर दिया। इसके बजाय, प्रत्येक अधिराज्य में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में एक गवर्नर-जनरल होना था, लेकिन केवल औपचारिक शक्तियों के साथ। गवर्नर-जनरल को संबंधित अधिराज्य की सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था।
- रियासतें, जो ब्रिटिश आधिपत्य के तहत अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र थीं, को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था।
- अधिनियम में दो नए अधिराज्यों के बीच ब्रिटिश भारत की आस्तियों और दायित्वों के विभाजन का प्रावधान किया गया था। इसमें सेना, सिविल सेवाओं और अन्य प्रशासनिक तंत्र का विभाजन शामिल था।
- जब तक नए संविधान नहीं बन जाते, तब तक भारत और पाकिस्तान का शासन भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के तहत चलाया जाना था, जिसमें आवश्यकतानुसार जरुरत के हिसाब से संशोधन किए जा सकते थे।
- अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान की मौजूदा संविधान सभाओं को उनके संबंधित संप्रभु विधायी निकायों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। ये सभाएँ दो नए राष्ट्रों के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थीं।

Sample Preview

भारतीय संविधान की प्रकृति

1. "भारतीय संविधान स्वरूप में संघीय लेकिन सार रूप में एकात्मक है"। टिप्पणी करें।

[UP PCSJ 2003]

Ans. भारतीय संविधान को अक्सर संघीय और एकात्मक विशेषताओं के एक अद्वितीय मिश्रण के रूप में वर्णित किया जाता है, जिससे इसे संघीय या एकात्मक संविधान के रूप में सख्ती से वर्गीकृत करना मुश्किल हो जाता है। यह कथन "भारतीय संविधान स्वरूप में संघीय लेकिन सार रूप में एकात्मक है" इस दोहरी प्रकृति को समाहित करता है। इसे कभी-कभी अर्ध-संघीय प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महासंघ और संघ दोनों के तत्व शामिल होते हैं। संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी, प्रशासनिक और कार्यपालिका शक्तियों के वितरण को निर्दिष्ट करता है। विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो संघ सरकार, राज्य सरकारों को प्रदत्त शक्तियों और उनके बीच साझा की गई शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं

1. शक्तियों का विभाजन
2. द्विसदनीय विधानमंडल
3. लिखित एवं कठोर संविधान
4. स्वतंत्र न्यायपालिका
5. दोहरी शासन प्रणाली

भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं

1. मजबूत केंद्र सरकार
2. एकल नागरिकता
3. राज्य की सीमाओं को बदलने की शक्ति
4. एकीकृत न्यायपालिका
5. आपात प्रावधान
6. राज्यपालों की नियुक्ति

Click Here to Buy Linking Publications

भारत का संविधान

साक्षात्कार प्रश्न – हल

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

भारत का संविधान

1. संविधानवाद क्या है?
उत्तर- संविधानवाद एक ऐसी राजनीति की अवधारणा है जो संविधान के भीतर है और जिसमें सरकार की शक्तियां सीमित और विधि के तहत हैं।

2. भारत का संविधान कब अपनाया गया था?
उत्तर- 26 नवंबर 1949 को।

3. भारत का संविधान कब लागू हुआ था?
उत्तर- सर, 26 जनवरी 1950 को।

4. उद्देशिका में पहला संशोधन कब किया गया था?
उत्तर- सर, 1976 में।

5. किस संशोधन अधिनियम द्वारा?
उत्तर- सर, 42वां संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1976।

6. क्या संशोधन किया गया?
उत्तर- सर, उद्देशिका में 'समाजवादी' 'धर्मनिरपेक्षता' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।

7. भारत एक 'राज्यों का संघ' है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है?
उत्तर- सर, अनुच्छेद 1 में।

8. किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ होने की तिथि निर्धारित की गई है?
उत्तर- सर, संविधान के अनुच्छेद 394 के तहत।

9. संविधान का नाम भारत का संविधान है। इसका उल्लेख कहाँ है?
उत्तर- सर, अनुच्छेद 393 में।

10. मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों में क्या अंतर है?
उत्तर- संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) में दिए गए अधिकार मौलिक अधिकार हैं, जबकि मानवाधिकार मौलिक अधिकारों से व्यापक हैं। सभी मौलिक अधिकार मानवाधिकार हैं लेकिन सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार नहीं हैं।

11. मौलिक अधिकारों को कब प्रतिबंधित किया जा सकता है?
उत्तर- (1) सशस्त्र बल के सदस्यों के संबंध में (अनुच्छेद 33)
(2) जबकि सैनिक विधि लागू है (अनुच्छेद 34)
(3) संविधान के संशोधन द्वारा (अनुच्छेद 368)
(4) आपातकालीन उद्घोषणा के दौरान (अनुच्छेद 358,359)

12. किस अनुच्छेद में 'राज्य' की परिभाषाएँ दी गई हैं?
उत्तर- सर, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में।

13. न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है?
उत्तर- न्यायिक पुनर्विलोकन वह शक्ति है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करता है। वे किसी भी विधि को लागू करने से इंकार कर सकते हैं जो संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत है।

14. न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है?
उत्तर- सर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत।

15. अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' शब्द में क्या शामिल है ?
उत्तर- अनुच्छेद 13 के प्रयोजनों के लिए, 'विधि' शब्द में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, अधिसूचना, विनियमन, रिवाज़ या प्रथा शामिल है।

16. विधि नियम का क्या अर्थ है?
उत्तर- विधि नियम का अर्थ है- कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति देश के सामान्य विधि और सामान्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

17. आप उत्तर प्रदेश (अन्य राज्य) के निवासी हैं इसलिए हम आपका चयन नहीं करते हैं? क्या यह संवैधानिक है?
उत्तर- सर जी नहीं, अनुच्छेद 16 (2) निवास स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।

18. अनुच्छेद 16(6) में क्या प्रावधान है?
उत्तर- सर, आर्थिक आधार पर सवर्णों को (103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा) 10% आरक्षण दिया गया है।

19. आरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद में है ?
उत्तर- सर, अनुच्छेद 16(4), 16(6) और 15(4), 15(6) में।

20. पिछड़ेपन का आधार क्या है ?
उत्तर- सर, जाति, प्रास्थिति, अवसर|

21. इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ AIR 1993 SC का फैसला कब हुआ था?
उत्तर- सर, 1993 में।

22. अनुच्छेद 20 के बारे में बताएं?
उत्तर- अनुच्छेद 20 उन अभियुक्त व्यक्तियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है जिन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है। इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक सुरक्षा इस प्रकार हैं –
(i) कार्योत्तर कानून से सुरक्षा
(ii) दोहरे दंड से सुरक्षा
(iii) आत्म-अभिसंशय से सुरक्षा

23. 'निमो डिबेट विस वेक्सारी" क्या है? या 'दोहरा दंड' क्या है?
उत्तर- सर, एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा चलाया और दंडित नहीं किया जा सकता है।

24. प्रावधान कहां है?
उत्तर- हाँ सर, अनुच्छेद 20 (2) के तहत।

25. दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी प्रावधान है ?
उत्तर- सर, धारा 300 के तहत।

26. अनुच्छेद 20 (2) और धारा 300 में क्या अंतर है?
उत्तर- अनुच्छेद 20 (2) में 'अभियोजन और दंड' वाक्यांश का उपयोग किया गया है, जबकि धारा 300 के तहत 'दोषी या दोषमुक्त' वाक्यांश है। यदि अभियुक्त दोषमुक्त हो जाता है, तो अनुच्छेद 20 (2) उसे सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

27. दंड प्रक्रिया संहिता का अनुच्छेद 20 (2) और धारा 300, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 से कैसे भिन्न है?
उत्तर- अनुच्छेद 20 (2) और धारा 300 आपराधिक कार्यवाही से संबंधित हैं। जबकि धारा 11 सिविल मामले से संबंधित है।

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

28. अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान है?

उत्तर- अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

29. 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का क्या अर्थ है?

Ans. व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक व्यापक श्रेणी की शब्दावली है और इसमें कई अधिकार शामिल हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का गठन करते हैं और उनमें से कुछ को विशिष्ट मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया है और अनुच्छेद 19 के तहत अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है।

30. किस संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है?

उत्तर- संविधान का 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002 (अनुच्छेद 21-ए)।

31. हर किसी को अपनी पसंद के वकील से सुरक्षा पाने का अधिकार है। संविधान में ये प्रावधान कहां है?

उत्तर- सर, अनुच्छेद 22 के तहत।

32. अनुच्छेद 22 के तहत क्या प्रावधान है?

उत्तर- अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

33. अभियुक्तों को संवैधानिक संरक्षण क्या हैं?

उत्तर-
(1) बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता।
(2) वकील से परामर्श करने का अधिकार
(3) अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार
(4) गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार
(5) कार्योत्तर विधि से सुरक्षा
(6) दोहरे दंड से सुरक्षा
(7) आत्म-अभियोजन से सुरक्षा।

34. जनहित याचिका (पीआईएल) कौन दायर कर सकता है?

उत्तर- कोई भी नागरिक या संस्था किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट दायर कर सकता है जो गरीबी या किसी अन्य कारण से न्यायालय में रिट दायर करने में सक्षम नहीं है।

35. जनहित याचिका (पीआईएल) के जनक कौन हैं?

उत्तर- सर, माननीय न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती।

36. जनहित याचिका (पीआईएल) क्या है?

उत्तर- जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए विधि का उपयोग है। यह वंचित समूहों या व्यक्तियों के वाद को आगे बढ़ाने में मदद करता है।

37. जनहित याचिका (पीआईएल) के क्या फायदे हैं?

उत्तर- यह न्यायालय के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। इससे कोई भी वर्ग या वर्ग के लोग अपनी याचिका के साथ न्यायालय जा सकते हैं।

38. जनहित याचिका (पीआईएल) की जननी कौन है?

उत्तर- सर, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। पीके हिंगोरानी एक भारतीय वकील थी जिन्हें जनहित याचिका की जननी माना जाता है। तत्कालीन प्रचलित कानूनों के अनुसार, याचिका केवल पीड़ित या रिश्तेदार द्वारा दायर की जा सकती है। कपिला और उनके पति निर्मल हिंगोरानी बिहार में विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे।

39. संविधान में जनहित याचिका (पीआईएल) का प्रावधान कहाँ है?

उत्तर- अनुच्छेद 32 और 226 में पीआईएल की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति पीएन भगवती द्वारा पेश (विकसित) किया गया है।

40. न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- न्यायालय कई जनहित मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है जो कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं और सरकार और अधिकारियों को संविधान और अन्य कानूनों के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की इस कार्रवाई को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है।

41. दया याचिका क्या है?

उत्तर- पुनर्विचार याचिका और उपचारात्मक याचिका जैसे सभी कानूनी और न्यायिक उपायों के समाप्त हो जाने के बाद, दया याचिका मौत की सजा पाने वाले दोषी के लिए उपलब्ध अंतिम उपाय है। दया याचिका मांगने के लिए निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।

42. क्या पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले या आदेश के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति किसी राहत का हकदार है?

उत्तर- हां सर, उपचारात्मक याचिका (सहमति से विवाह विच्छेद के मामले में, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्राकेस (2002 SC) से उपचारात्मक याचिका की अवधारणा सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित की गई थी।)

43. उपचारात्मक याचिका क्या है?

उत्तर- सर, अंतिम सजा के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय का हनन न हो और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके।

44. उपचारात्मक याचिका कौन दायर कर सकता है

उत्तर- अंतिम सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। इस पर विचार किया जा सकता है यदि याचिका यह स्थापित करती है कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था और आदेश पारित करने से पहले न्यायालय द्वारा उसकी सुनवाई नहीं की गई। यह नियमित के बजाय दुर्लभ होना चाहिए।

45. पुनर्विचार याचिका और उपचारात्मक याचिका में क्या अंतर है?

उत्तर- पुनर्विचार याचिका और उपचारात्मक याचिका के बीच मुख्य अंतर यह है कि पुनर्विचार याचिका भारत के संविधान में स्वाभाविक रूप से प्रदान की जाती है जबकि उपचारात्मक याचिका का उद्भव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका अनुच्छेद 137 में निहित की व्याख्या के संबंध में है।

46. क्या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को भी न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार के लिए चुनौती दी जा सकती है?

OR / या

उपचारात्मक याचिका क्या है?

उत्तर- सर, उपचारात्मक याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, AIR 2002 SC 1771 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय अपने अंतिम निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है जिसे रिट याचिका द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है।

Sample Preview
Click Here to Buy Linking Publications

न्यायाधीशों की नियुक्ति के सात चरण होते हैं -

(1) **उच्च न्यायालय का कॉलेजियम** - तीन न्यायाधीश कॉलेजियम बनाते हैं अर्थात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश।

(2) **सिफ़ारिश भेजना -** उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य सरकार और राज्यपाल को सिफ़ारिश भेजेंगे।

(3) **राज्यपाल केंद्रीय कानून मंत्री को रिपोर्ट भेजते हैं-** राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद अपनी टिप्पणी के साथ केंद्रीय कानून मंत्री को रिपोर्ट भेजते हैं।

(4) **केंद्रीय कानून मंत्री सीजेआई को -** केंद्रीय कानून मंत्री प्रस्ताव पर विचार करने के बाद पूरे विचार के साथ प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजेंगे।

(5) **सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम -** न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से गठित होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श के बाद प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्री को भेजेंगे

(6) **प्रधान मंत्री से राष्ट्रपति -** केंद्रीय कानून मंत्री का तात्पर्य प्रधान मंत्री से होगा जो नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देगा।

(7) **राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति-** राष्ट्रपति वारंट पर हस्ताक्षर करेगा। चयनित व्यक्ति का नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच पत्राचार लिखित रूप में होगा।

Sample Preview

About the Linking App

Linking App Features

Get all E-Book of
- Linking Charts
- Paperathon Booklets
- Study Material E-Notes
- Free Video Lectures Links

How to use Linking App

- Register Yourself then Login
- Subscribe to the plan on validity basis (i.e. 1 Month, 6 Months or 12 Months)
- Go to My Courses
- Get access to all Linking Publications

How to download Linking App

You can download Linking App via Play Store GET IT ON Google Play

If you can't find the App on Play Store Kindly use this QR Code to download the App.

Click Here to Buy Linking Publications

ALL-IN-ONE PAPERATHON©

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams.

Available in English and Hindi Edition

Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at **Linking App.**

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications

Linking Paperathon Booklets

Unique Features of Paperathon Booklet

- Subject-wise presentation with weightage analysis table
- Covered Last Previous Years Papers
- Linked Provision
- Diglot Q&A (English + Hindi)
- Explanation (English + Hindi)
- QR Code for Paper Solution Free Videos
- QR Code for Free Videos Lectures for All Judiciary & Law Exams

Linking Charts

Major Laws Linking Charts | New Criminal Laws Linking Charts | Alpha Minor Laws Linking Charts

Scan this QR Code Place Order

Linking Bare Acts

Sample Preview

Click Here to Buy Linking Publications